

केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिये वित्तपोषण तथा क्रयान्वयन को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- 44 हजार 605 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, नवादा, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, वदिशा और रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी।
- इस परियोजना के लिये केंद्रीय समर्थन के रूप में 39 हजार 317 करोड़ रुपए, सहायक अनुदान के रूप में 36 हजार 290 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूर किया गया है। यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत मूलरूप लेने वाली केन-बेतवा लकि परियोजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बहारी वाजपेयी के स्वप्न के रूप में एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है।
- परियोजना की वसित्तु डी.पी.आर. तैयार करने हेतु मध्य प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।
- इस परियोजना से नमिनलखिति लाभ होंगे-
 - परियोजना के मूलरूप लेने पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सचिई सुवधि उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा तथा सूखा की समस्या खत्म होगी।
 - जल संकट से प्रभावित प्रदेश की 41 लाख आबादी को पेयजल की सुवधि प्राप्त होगी।
 - परियोजना से भू-जल स्तर की स्थिति सुधरेगी।
 - परियोजना से 103 मेगावाट बजिली का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग पूर्णरूप से मध्य प्रदेश करेगा।
 - जल आपूर्ति होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगीकरण एवं नविश को बढ़ावा मल्लिगा। तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
 - स्थानीय स्तर पर आमजन में आत्मनिर्भरता आएगी तथा क्षेत्र से लोगों का पलायन रुकेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मल्लिगा।
 - इस परियोजना से पन्ना जिले में 70 हजार हेक्टेयर, छतरपुर में 3 लाख 11 हजार 151 हेक्टेयर, दमोह में 20 हजार 101 हेक्टेयर, टीकमगढ़ एवं नवादा में 50 हजार 112 हेक्टेयर, सागर में 90 हजार हेक्टेयर, रायसेन में 6 हजार हेक्टेयर, वदिशा में 20 हजार हेक्टेयर, शिवपुरी में 76 हजार हेक्टेयर एवं दतिया जिले में 14 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सचिति हो सकेगा। साथ ही पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध होगा।